

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(1)ग्रावि/नरेगा/स्कीम/2012

जयपुर, दिनांक :

4 MAY 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :-ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में किये गये संशोधन के क्रम में।

संदर्भ :- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.05.2012 को जारी अधिसूचना।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.05.2012 को अधिसूचना जारी कर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 एवं 2 में संशोधन किया गया है। जारी अधिसूचना की प्रति केन्द्र सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिसूचना से किए गए संशोधन के आधार पर अद्यतन अनुसूची 1 एवं 2 भी केन्द्र सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके तहत किए गए संशोधन का सारांश निम्नानुसार है :-

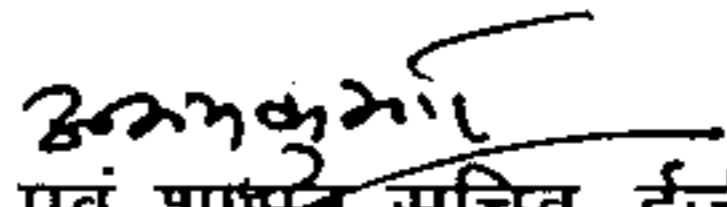
- योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में विस्तार किया गया है एवं इसमें नये/अतिरिक्त कार्य सम्मिलित किए गए हैं। कार्यों की प्राथमिकता ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा एवं वार्ड सभा की बैठक में तय की जायेगी।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर सामग्री मद की लागत कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उक्त संशोधनों के अनुरूप नये/अतिरिक्त कार्यों के संबन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा मार्ग दर्शिका भी जारी की गई है एवं यह भी केन्द्र सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधन, इन संशोधनों के अनुरूप नरेगा अधिनियम की अनुसूची 1 एवं 2, नये/अतिरिक्त अनुमत कार्यों की मार्ग दर्शिका की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि योजना से जुड़े आपके अधीनस्थ सभी विभागों, कार्यक्रम अधिकारियों ग्राम पंचायतों एवं अन्य अधिकारियों आदि को किए गए संशोधनों की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उसके अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जावे।

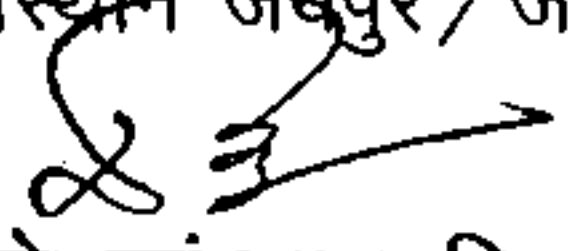
भवदीय

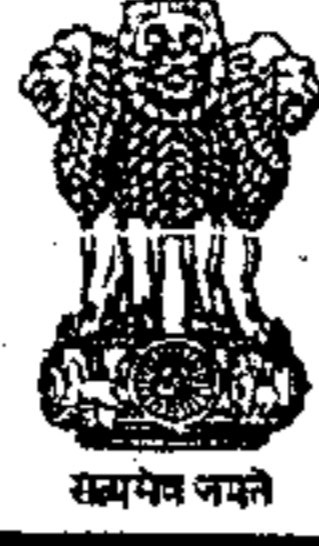
संलग्न: उपरोक्तानुसार।


आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।


परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 859]
No. 859]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2012/वैशाख 14, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2012/VAISAKHA 14, 1934

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2012

क्र.अ. 1022(अ).— केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और सनीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में,—

(i) पैरा 1ख के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :

“1ख. स्कीम के केंद्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों पर होगा और उसकी पूर्विकता क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभा के अधिदेशनों में आधारित किया जाएगा, अर्थात् :—

- (i) जल संरक्षण और जल सस्य संवय, जिसके अंतर्गत कन्दूर खाइयां, कन्दूर बांध, मोलशुभ्र धेक, गांधयन संरचनाएं, भूमिगत नहरें मिट्टी के बांध, स्टीप बांध और झरनों का विकास भी हैं ;
- (ii) सूखारोधी, जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी है ;
- (iii) सिंचाई नहरें, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं ;
- (iv) पैरा 1ग में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वाभित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर छोटा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंघन और भूमि विकास का उपबंध ;

- (v) पारम्परिक जल निकासों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है ;
- (vi) भूमि विकास ;
- (vii) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का संनिर्माण ;
- (viii) सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़कें भी हैं ;
- (ix) ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण सजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण ;
- (x) एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्विड बायो-मेन्बोर जैसे कृषि संबंधी संकर्म ;
- (xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म ;
- (xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकासों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबंधी संकर्म ;
- (xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म ;
- (xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म ;
- (xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म ;
- (xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचित किया जाए ;

(ii) पैरा 1ख के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“1ख. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण सहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छेदे या सीमांत कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह संपदा पर अनुज्ञात किए जाएंगे।

1घ. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में निर्दिष्ट संकर्मों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) पैरा 1ग में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा ; और

(ख) हिताधिकारी, उनकी भूमि या गृह संपदा पर की जाने वाली परियोजना पर कार्य करेंगे।

(iii) पैरा 3 के उपपैरा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(घ) प्रत्येक मस्टर रोड की विशिष्ट पहचान संख्या होगी और उसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उसमें ऐसी अनिवार्य जानकारी अंतर्विष्ट होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ;”

(iv) पैरा 4 का लोप किया जाएगा ;

(v) पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“5. राज्य सरकार, स्कीम के भाग के रूप में, स्कीम के अधीन सृजित लोक आस्तियों के उचित रखरखाव की व्यवस्था करेगी।”;

(vi) पैरा 6 का लोप किया जाएगा ;

(vii) पैरा 7 में, “जब मजदूरी का कार्य की मात्रा से सीधा संबंध हो तब मजदूरी, राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार संदत्त की जाएगी।” शब्दों के स्थान पर, “राज्य सरकार मजदूरी को कार्य की मात्रा से संबद्ध करेगी और राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार संदत्त की जाएगी।” शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) पैरा 8 के उपपैरा (1) में, “नौ घंटे” शब्दों के पूर्व, “विश्राम के एक घंटे सहित”, शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ;

(ix) पैरा 9 में, “कुल परियोजना लागत” शब्दों के पूर्व, “प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर”, शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ;

(x) “भारत सरकार” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “केंद्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में,-

(i) पैरा 2 के उपपैरा (1) की मद (x) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(xi) आधार संख्या, यदि जारी की गई हो,.”;

(ii) पैरा 14 में, “ऐसी त्रिज्या” शब्दों के स्थान पर, “पैरा 12 में विनिर्दिष्ट त्रिज्या” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) पैरा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“15. नियोजन की अवधि कम से कम लगातार चौदह दिन की और एक सप्ताह में छह दिन से अनधिक की होगी।”;

(iv) पैरा 31 में, “मजदूरी का भुगतान” शब्दों के पश्चात् “, यदि इस प्रकार छूट न दी गई हो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. जे-11013/1/2011-एमजीएनआईजीए-1(भाग 7)]

डॉ. को. जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण 1 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 1 को पहले अधिसूचना सं० का०आ० 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं० द्वारा संशोधित किया गया :

1. का०आ० 88(अ), तारीख 14 जनवरी, 2008
2. का०आ० 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008
3. का०आ० 3000(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2008
4. का०आ० 1824(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009
5. का०आ० 1860(अ), तारीख 30 जुलाई, 2010
6. का०आ० 1484(अ), तारीख 30 जून, 2011
7. का०आ० 2202(अ), तारीख 22 सितंबर, 2011

टिप्पण 2 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 2 को पहले अधिसूचना सं० का०आ० 324 (अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं० द्वारा संशोधित किया गया :

1. का०आ० 802 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2008
2. का०आ० 2188(अ), तारीख 11 सितंबर, 2008
3. का०आ० 2999(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2008
4. का०आ० 513(अ), तारीख 19 फरवरी, 2009
5. का०आ० 2266(अ), तारीख 30 सितंबर, 2011

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th May, 2012

S.O. 1022(E)— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) (herein referred to as the said Act), the Central Government on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments to Schedule I and Schedule II to the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

2. In the said Act, in SCHEDULE I, -**(i) for paragraph 1B, the following paragraph shall be substituted, namely:-**

“1B. The focus of the Scheme shall be on the following works and the order of priority shall be determined by each Gram Panchayat in meetings of the Gram Sabha and the Ward Sabha, namely:-

- (i) water conservation and water harvesting including contour trenches, contour bunds, boulder checks, gabion structures, underground dykes, earthen dams, stop dams and springshed development;
- (ii) drought proofing including afforestation and tree plantation;
- (iii) irrigation canals including micro and minor irrigation works;
- (iv) provision of irrigation facility, dug out farm pond, horticulture, plantation, farm bunding and land development on land owned by households specified in paragraph 1C;
- (v) renovation of traditional water bodies including desilting of tanks;
- (vi) land development;
- (vii) flood control and protection works including drainage in water logged areas including deepening and repairing of flood channels, chaur renovation, construction of storm water drains for coastal protection;
- (viii) rural connectivity to provide all weather access, including culverts and roads within a village, wherever necessary;

16334/12-2

- (ix) construction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra as Knowledge Resource Centre at the Block level and as Gram Panchayat Bhawan at the Gram Panchayat level;
- (x) agriculture related works, such as, NADEP composting, vermi-composting, liquid-bio-manures;
- (xi) livestock related works, such as, poultry shelter, goat shelter, construction of pucca floor, urine tank and fodder trough for cattle, azolla as cattle-feed supplement;
- (xii) fisheries related works, such as, fisheries in seasonal water bodies on public land;
- (xiii) works in coastal areas, such as, fish drying yards, belt vegetation;
- (xiv) rural drinking water related works, such as, soak pits, recharge pits;
- (xv) rural sanitation related works, such as, individual household latrines, school toilet units, anganwadi toilets, solid and liquid waste management;
- (xvi) any other work which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government.”;

(ii) after paragraph 1B, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

“1C. All activities mentioned in items (iv), (x), (xi) and items (xiii) to (xv) of paragraph 1B shall be allowed on land or homestead owned by households belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes or below poverty line families or the beneficiaries of land reforms or the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India or that of the small or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008, or the beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007).

1D. The works referred to in items (iv), (x), (xi) and items (xiii) to (xv) of paragraph 1B shall be taken up subject to the following conditions, namely:-

- (a) the households referred to in paragraph 1C shall have the job card; and
- (b) the beneficiaries shall work on the project undertaken on their land or homestead.”;

(iii) in paragraph 3, for sub-paragraph (d), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(d) Each muster roll shall have a unique identity number and be certified by the Programme Officer and shall contain such mandatory information as may be specified by order, by the Central Government.”;

(iv) paragraph 4 shall be omitted;

(v) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“5. As part of the Scheme, the State Government shall provide for proper maintenance of the public assets created under the Scheme.”;

(vi) paragraph 6 shall be omitted;

(vii) in paragraph 7, for the words, “when wages are directly linked with the quantity of work, the wages shall be paid”, the words, “The State Government shall link the wages with the quantity of work and it shall be paid” shall be substituted;

(viii) in paragraph 8, in sub-paragraph (1), after the words “for nine hours”, the words “including an hour of rest” shall be inserted;

(ix) in paragraph 9, after the words “project costs”, the words “at the level of each Gram Panchayat” shall be inserted;

(x) for the words “Government of India”, wherever they occur, the words “Central Government” shall be substituted.

3. In the said Act, in SCHEDULE II,-

(i) in paragraph 2, in sub-paragraph (1), after item (x), the following item shall be inserted, namely:-

“(xi) Aadhaar number, if issued.”;

(ii) in paragraph 14, for the words “such radius”, the words “the radius specified in paragraph 12” shall be substituted;

(iii) for paragraph 15, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“15. A period of employment shall be at least continuous fourteen days with not more than six days in a week.”;

(iv) in paragraph 31, after the word “shall”, the words “unless so exempted” shall be inserted.

[F. No. J-11013/1/2011-MGNREGA-I (Pt. VII)]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

Note 1 : Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide number S.O. 323(E), dated the 6th March, 2007, and subsequently amended vide following notification numbers:

1. S.O. 88(E), dated the 14th January, 2008
2. S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008
3. S.O. 3000(E), dated the 31st December, 2008
4. S.O. 1824(E), dated the 22nd July, 2009
5. S.O. 1860(E), dated the 30th July, 2010
6. S.O. 1484(E), dated the 30th June, 2011
7. S.O. 2202(E), dated the 22nd September, 2011

Note 2 : Schedule II of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide number S.O. 324(E), dated the 6th March, 2007, and subsequently amended vide following notification numbers:

1. S.O. 802(E), dated the 2nd April, 2008
2. S.O. 2188(E), dated the 11th September, 2008
3. S.O. 2999(E), dated the 31st December, 2008
4. S.O. 513(E), dated the 19th February, 2009
5. S.O. 2266(E), dated the 30th September, 2011

GUIDELINES FOR THE NEW / ADDITIONAL WORKS PERMITTED UNDER MGNREGA

To strengthen the positive synergy between MGNREGA and agriculture and allied rural livelihoods, to respond to the demands of the States for greater location specific flexibility in permissible works and to help improve the ecological balance in rural India and to provide a cleaner, healthier environment for the rural population, it has been decided to expand the list of permissible works as under.

The MGNREGA Schedule I & II have been amended accordingly.

While implementing these works, the following should be adhered to:

1. All works shall be approved by the Gram Sabha and the Gram Panchayat and shall be part of the Annual Shelf of Projects.
2. The unit costs included in the works below are indicative and project costs for each work will be estimated depending on the Schedule of Rates (SoR's) prevalent in the respective region/area of work.
3. All activities mentioned in items (iv), (x), (xi) and items (xiii) to (xv) of paragraph 1B of Schedule I of the Act, shall be allowed on land or homestead owned by households belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or below poverty line families or the beneficiaries of land reforms or the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India or that of the small or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008, or the beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) .
4. For works to be taken up on private land and homestead, the individual land owner shall be a job card holder and also work in the project.
5. It should be ensured that the total material cost (including wages of skilled and semi-skilled workers) of all works in the Annual Shelf of Projects (including the works suggested under Para 1C of Schedule I taken up in a Gram Panchayat, in a Financial Year, should not exceed 40 %
6. Only those components of admissible works that lead to creation of durable assets may be taken up under MGNREGA. Items of expenditure that are recurring in nature and/or do not lead to creation of durable assets, are not permitted under MGNREGA.

A. WATERSHED RELATED WORKS

1. CONTOUR TRENCH

In the ridge area of a watershed a contour trench is a simple and inexpensive solution to slowing down surface runoff and reducing soil erosion. A contour trench is a trench dug along a contour line. A contour line is an imaginary line that joins together points of the same elevation. Since the trench is dug along a line that is at the same elevation, this increases the chance of holding the runoff water for a longer time within the trench. If trenches were not to follow a contour, such digging could actually increase the possibility of soil erosion because there would be a rise in the velocity of runoff following upon an increase in the slope of the land.

Contour trenches are constructed in non-arable ridge area i.e. land not suitable for cultivation and with higher land slope (10 to 25%).

Unit cost of a contour trench of dimensions 0.5m*0.5m in staggered design comes to around Rs. 11,000 per hectare. In terms of running length, the cost comes to Rs. 17 per running metre. The unskilled labour cost is 100% of the total cost.

2. CONTOUR BUND

Contour bunds are a simple and low-cost method of checking the velocity of runoff in the ridge area of any watershed. A contour bund is a bund constructed along a contour line. A contour line is an imaginary line which joins together points of the same elevation. Making a bund along a line that is at the same level increases the chances of containing runoff for a longer period of time within the bund. Like contour trenches, bunds also collect the rainwater that falls in the ridge area. This way the soil moisture profile in the area adjacent to the bund is improved. Along with the water, eroded fertile topsoil also gets deposited in the bund. It is, therefore, important to combine contour bunds with appropriate vegetative measures.

Contour bunds are constructed in arable area i.e. land suitable for cultivation and land slope ranging from 3-10%. Waste-weirs at suitable location for safe disposal of excess rain water are to be constructed with contour bunds. Therefore construction of waste weir should be part of contour bunds.

For a contour bund of height 0.6m, base width of 2.0m and a cross-sectional area of 0.66 sq.m., the unit cost comes to around Rs. 14,000 per hectare. In terms of running length, the cost comes to about Rs. - 42 per running metre. The unskilled labour: material cost comes to 85:15.

3. BOULDER CHECK

Boulder checks are loose rock dams made on small drainage lines or seasonal streams which have very small catchment area of less than 50 ha. The main aim of constructing loose boulder checks is to reduce the velocity of water flowing through the drainage line. By reducing the velocity of runoff, boulder checks help in reducing soil erosion; trapping silt which slows the rate of siltation in water harvesting structures in the lower reaches of the watershed; creating a hydraulic head locally which enhances infiltration of surface runoff into the groundwater system; and increasing the duration of flow in the drainage line. Therefore, the capacity of the water harvesting structures created downstream on the drainage line is utilised more fully as they get many more refills.

The unit cost of a loose boulder check of 7m length, maximum height of 1m, upstream and downstream slopes 1:1 and 3:1 and top width of 0.5m comes to around Rs. 4000. In the case boulders are available within 200 metres lead, the unskilled labour cost would be 100% of the total cost

4. FARM BUNDING

Farm bunds are constructed on agricultural land with the aim of arresting soil erosion and improving the soil moisture profile. Ideally, bunds on farms should be made on the contour line. However, farmers do not easily accept this as it creates several problems. Contour bunds divide the field into irregular sections. In such a situation, it becomes inconvenient to maneuver bullocks for operations such as ploughing and line-sowing. Due to these difficulties, what is normally practiced in the name of farm bunding is bunding along the field boundaries. However, bunding along the field boundaries should be restricted to only field boundaries falling across the field slope and with waste weir at suitable locations for safe disposal of excess run-off water. Bunds along the slopes are not very useful for arresting soil erosion or conserving moisture. By dividing the field into several units, bunds control the volume and velocity of runoff in each such unit. The water in the field and the soil it is carrying are stopped at each bund. Thus, by not allowing water a long stretch of free flow, bunds break the momentum of water. Bunding improves and stabilises the soil moisture profile.

For a standard farm bund of height 0.6m, base width 1.7m and cross section area of 0.57 sq.m., the unit cost comes to around Rs. 8000 per hectare. In terms of running length, the cost comes to around Rs. 40 per running metre. The unskilled labour: material cost is 85:15. This activity is only for those households eligible under MGNREGA for work on private land.

5. GABION STRUCTURES

Gabion structures are rock and wire dams constructed across drainage lines with a catchment area of 50-500 ha. They are also constructed to reinforce highly erodable stream embankments. The main aim of constructing gabion structures is to reduce the velocity of water flowing through the drainage line. By reducing the velocity of runoff, gabion structures help in reducing soil erosion, trapping silt, which reduces the rate of siltation in water harvesting structures in the lower reaches of the watershed, increasing recharge of groundwater and increasing the duration of flow in the drainage line. Therefore, the capacity of the water harvesting structures created downstream on the drainage line is utilised more fully as they get many more refills.

There are two ways of reinforcing a loose boulder structure with wire mesh: a) to make the structure as per the dimensions of the design and wrap it with wire mesh on all sides except the bottom. This wrap is partially anchored under the bottom; and b) to cage the boulders in rectangular boxes. The structure would be made up of several such boxes tied together. In such a structure the wire mesh not only provides a covering shell, it also gives horizontal and vertical reinforcements within the structure. The second method is superior to the first in terms of strength and it is economical in the use of boulders, although more wire mesh is used than in the first method.

The cost of a gabion structure of 2 m height, 1m top width and 12 m length works out to about Rs. 45000. The unskilled labour:material ratio is 30:70.

6. UNDERGROUND DYKE

Underground dykes are earthen dams that obstruct the flow of this sub-surface water and divert them to nearby wells and tubewells. Dykes do not submerge any land. Nor is the water stopped by them subject to evaporation. Underground dykes are most suited to hard rock areas where impermeable strata are often found at shallow depths below the surface and in areas where the soil required to fill up the dyke is relatively easily available. The main objectives of constructing underground dykes are to impede the flow of sub-surface water and make it available in the watershed for a longer period; to increase the water level in wells by redirecting this sub-surface water to nearby wells and tubewells; and to make surface flows in the drainage line available for a longer period.

The cost of an underground dyke of 12m length, 6m maximum depth and 2m top width works out to around Rs. 43000. The unskilled labour : material ratio is 70:30.

7. EARTHEN DAM

The most important structures of any watershed programme are the earthen dams built on the main stream of the watershed. Most parts of India typically receive rainfall between June and September, very intensely within a few hours and a few days. The number of rainy days does not average more than 40-50. Moreover, rains are extremely erratic, often characterised by late onset and early withdrawal. Prolonged dry spells during the rainy season, resulting in agricultural droughts, are also frequent. Hence, the kharif crop needs to be drought-proofed through 'protective' irrigation, applied to overcome accumulated soil moisture deficits within the rainy season. Earthen dams are especially important in areas which are poor in groundwater resources and which do not have access to canal irrigation. Such areas form about half of India's agricultural area. Earthen dams can also be constructed as percolation structures, to enhance the rate of groundwater recharge. Such percolation structures are usually made on the upper part of the catchment area. Water stored here percolates to wells and tubewells located in the lower part of the catchment. Such percolation dams can also be made in the immediate upstream portion of wells and tubewells.

The cost of an earthen dam of 65 m length, maximum height of 4.65 m, upstream and downstream slopes of 2:1 and 2.5:1 and a top width of 2m works out to around Rs. 2.6 lakhs. In general the unit cost works out to Rs. 20-30 per cum. of water stored. The unskilled labour : material ratio is 95:5.

This is an activity that can be undertaken on public land only.

8. DUGOUT FARM PONDS

Dugout farm ponds (DOP) are made on private land to harvest runoff from very small local catchments. The main reason for making a DOP is to collect rainwater, which would otherwise have flowed out of the field. There are several days in succession in the monsoon when there is no rainfall. Such prolonged dry spells may actually ruin the kharif crop. The DOP protects against such crop failure. Unlike the earthen dams, DOP is relatively free of topographical constraints. On flatter land in the village, streams are not very deep, nor do they have high embankments. Thus it becomes difficult to build water harvesting structures like earthen dams. In such flat lands, DOPs are the most effective water harvesting solution. The main objective of such structures is to provide protective irrigation to the kharif crop. In addition, in West

Bengal, Assam, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand and Orissa, DOPs have been traditionally used to irrigate the rabi crop and also for fish farming.

The cost of a DOP of 25m*20m*2m dimensions (1000 cubic metre storage capacity) works out to around Rs. 1,00,000. In general the unit cost works out to Rs. 50-60 per cum. of water stored. The unskilled labour cost is 100% of the total cost.

This activity is only for those households eligible under MGNREGA for work on private land.

9. STOP DAM

Stop dams are constructed on streams with big catchments. They are designed to capture the post monsoon flows. Usually, the gates of the stop dam are kept open during the monsoon season to let out runoff water. This also ensures that there is little or no siltation in the stop dam. After the monsoon, the gates are closed and the dam gets filled up with post monsoon flows. Hence, such dams should be constructed only in streams with perennial flows so that the stop dam gets several re-fills during the post-monsoon season.

For a stop dam with a catchment area of 1000 hectares, length of 20m, maximum height of 2.7m, top width of 1.5m and side slopes of 1:1, the cost works out to around Rs. 5 lakhs. In general the unit cost works out to Rs. 90-100 per cum. of water stored. Stop dams are masonry dams either using bricks or stone. Where hard stones (compact basalt or granite) are available in sufficient quantity, it is good to use random rubble stone masonry. Also used are pre-fabricated metal sheets of 1.5 mm thickness for the gates of stop dams. The unskilled labour : material ratio works out to 25:75.

Full technical details of all structures in this section are available in manuals of the Ministry of Rural Development, Government of India. These can be accessed at <http://www.nrega.nic.in>

B. WATERSHED RELATED WORKS IN MOUNTAIN REGIONS

10. SPRINGSHED DEVELOPMENT

Regenerating springs' discharge in mountain regions is critical because they are the sources of most rural and urban water supply systems. Larger springs are also used for irrigation. A springshed is the area of a mountain slope that feeds water to a spring through underground seepages. Springshed (sometimes also referred to as spring sanctuaries) development can help enhance rainfall infiltration into the ground, recharge springs, revive dysfunctional traditional water harvesting systems, moderate flood peaks and recharge streams and rivers. Springshed development includes a number of interventions that are typical of watershed development, e.g., trenching, planting of trees, fodder grasses or hedges and gully plugging. The typical size of a springshed ranges from as little as a couple of hectares to about 20 ± 5 hectares.

The unit cost of springshed development depends on the location, slope, and the types and number of interventions. It is estimated that the costs can range from about Rs. 18,000 to Rs. 38,000 per hectare depending on the combination of proposed interventions. The labour to material ratio can vary from 90:10 upto 60:40. For example, a combination of staggered trenches and fuel/fodder tree plantation on <30% slope costs about Rs.22,000 per hectare with a labour: material ratio of 70:30. Staggered trenches on

terraced fields with fruit trees plantations may cost about Rs. 38,000 with a unskilled labour: material ratio of 90:10.

Details of a springshed development programme can be seen at www.sikkimsprings.org.

C. AGRICULTURE RELATED WORKS

11. NADEP COMPOSTING

Revitalizing soil health holds the key to improving productivity of Indian agriculture. *Composting* is a process of utilising and processing solid waste through which its organic component is biologically decomposed to a humus-like state that can be used as fertiliser. Solid wastes usually contain the entire range of micro-organisms in large numbers. Under appropriate conditions, the microbial population grows and in doing so, degrades the organic portion of the waste.

NADEP composting involves the construction of a 3.6m*1.5m*0.9m compost trough, which can produce 1 tonne of composted manure in each cycle. This manure is sufficient to cover 0.25 hectare of agricultural land. The NADEP pit is usually constructed with a lattice brick wall to ensure proper aeration. Inside this trough a series of layers of agricultural waste, dung and soil are successively heaped upon each other. About 100-110 kg of agricultural waste is first placed on the ground in a layer which is about 6 inches high. 4 kg of dung mixed in 125-150 litres of water is applied on top of this layer (the quantity of water used varies with the seasonal temperature, more water being necessary in the summer months). On top of the second layer, cleaned and sifted soil (roughly half the weight of the agricultural waste used, i.e. 50-55 kg) free of stones, glass etc. is spread on which a little water is also sprinkled. In this manner successive layers are heaped to a height of about 1.5 ft. above the top of the trough. After this the top of the pile is sealed with a 3 inch plastering of soil mixed with dung (400-500 kg). Within 2-3 months dark brown, friable, soft and moist compost, free of all foul odours is ready. It has been generally estimated that by the NADEP method, one head of cattle produces 80 tonnes of manure in a year. The nutrient status of this manure is Nitrogen 0.5-1.5%, Phosphorous 0.5-0.9% and Potassium 1.2-1.4%.

The unit cost of a NADEP pit of 3.6m*1.5m*0.9m is estimated at around Rs. 8000. The unskilled labour : material ratio of this work is 25:75.

Selection of households to be taken up for this activity under MGNREGA will be made only from those households eligible under MGNREGA for work on private land. Before taking up a second NADEP pit for any household under MGNREGA, it must be first ensured that all eligible MGNREGA households willing to take up this work have been covered with one NADEP pit.

12. VERMI-COMPOSTING

Vermi-composting uses earthworms to turn organic wastes into very high quality compost. In ideal conditions worms can produce at least their own weight of organic matter in a day. The micro-organisms in the worm casts promote healthy plant growth. Usually, a twin pit model is used for vermi-composting, with the pit size of 3.6m*1m*0.75m and with a dividing wall in the middle. Vermi-composts are best suited for intensive application in kitchen gardens and small vegetable plots. One vermi-compost pit produces 0.15 tonne of compost, which is sufficient for enhancing productivity of 0.25 hectare (2500 sq.m.).

The unit cost of one vermi-compost pit comes to around Rs. 9000, with a labour : material ratio of 25:75.

Selection of households to be taken up for this activity under MGNREGA will be made only from those households eligible under MGNREGA for work on private land. Before taking up a second vermi-compost pit for any household under MGNREGA, it must be first ensured that all eligible MGNREGA households willing to take up this work have been covered with one vermi-compost pit.

13. LIQUID BIO-MANURES: SANJEEVAK OR AMRIT PAANI

Sanjeevak is a liquid manure application based on cattle-urine. This low cost and effective method has immense potential to improve plant nutrition. In a brick masonry pit of 1m*1m*1m, 50 kg of cow dung, 20 litres of cattle urine, 1 kg jaggery and 1 kg of chickpea flour is mixed with 1000 litres of water. This solution is fermented for 5 to 7 days. This solution should be shaken regularly three times a day. After 7 days, the liquid manure of 1000 litres is diluted and applied on the field. This liquid manure can be mixed with irrigation water (fertigation) at the time when crops are irrigated. This ensures an even spread of the manure in the field. It can also be used in vegetable plots and kitchen gardens. The pit can be filled again and within the next 15 days another round of Sanjeevak can be applied to the crop.

The unit cost of one Sanjeevak pit is around Rs. 2000. The unskilled labour : material ratio is 30:70. This activity is only for those households eligible under MGNREGA for work on private land. A maximum of 3 Sanjeevak pits will be constructed per selected household under MGNREGA.

D. LIVESTOCK RELATED WORKS

To improve the participation of the poor and disadvantaged sections in the fastest growing segment of India's agrarian economy, viz., the livestock sector, we propose to permit the following works under MGNREGA:

14. POULTRY SHELTER

Backyard poultry helps in supplementing income as well as for providing much needed nutritional inputs for rural households. Poultry birds suffer from very poor shelter infrastructure available in villages leading to their poor health and frequent illnesses. High mortality amongst birds results in high losses and unpredictable and low incomes. To protect the birds from predators and frequent illnesses a pucca structure is required to act both as a night shelter and to provide protection to birds and eggs from predators.

A shelter of 7.50 sq m. (length 3.75 m and width 2 m) would be suitable for 100 birds. On the longer sides, the shelter will have a 30 cm high and 20 cm thick brick masonry wall upto plinth level. From the plinth to the top of the shelter there is a wire mesh supported by brick masonry pillars of size 30 cmx30 cm. The shorter side will have a 20 cm thick brick masonry wall with an average height of 2.20 metres. The roof will be supported by a steel truss. The roof will have galvanised iron corrugated sheets. The base of the floor will be constructed by hard moorum filling. The floor will be built by using 2nd grade bricks with packing in 1:6 ratio of cement mortar.

The total cost of such a poultry shelter is around Rs. 40,000. The poultry shelter will have a unskilled labour : material cost ratio of 20:80.

The hope is that gradually this would enable these households to move away from MGNREGA and make a living from poultry. Selection will be made only from those households eligible under MGNREGA for work on private land. Priority should be accorded to landless households.

15. GOAT SHELTER

Most poor rural households, who depend on small ruminants, lack the resources to construct and provide for an adequate and safe living space for their cattle. It is well known that for tribals of Central India goats and poultry are often more important as a means of livelihood than even minor forest produce. Lack of a safe living space leads to their poor health, frequent illnesses and to their maintaining a very low and uneconomical herd size. In the integrated farming systems of tribal households, the "waste" from livestock systems, such as cow dung, goat litter and urine are important organic inputs into agricultural farms, increasing soil fertility and raising crop output. Poor shelter infrastructure leads to low and inefficient collection of dung and urine, which is a waste of valuable and locally available organic inputs to farming. Thus, provision of better shelter facilities for cattle offers a win-win situation by which animal health and soil health can be improved simultaneously, with very low initial investments. It is one of the most suitable and accepted means of livelihood for the landless.

A 7.5 sq m. shelter (length 3.75 m and width 2 m) would be suitable for 10 animals. The 4 walls will be raised to an average height of 2.20 metres. The walls will be of brick masonry using 1:4 cement mortar. The roof will be supported by a steel truss. The roof will have galvanised iron corrugated sheets. The floor will be of hard moorum.

The cost of such a goat shelter will be around Rs. 35,000. The goat shelter will have a unskilled labour:material ratio of 25:75.

The hope is that gradually this would enable these households to move away from MGNREGA and make a living from poultry. Selection will be made only from those households eligible under MGNREGA for work on private land. Priority should be accorded to landless households.

16. CONSTRUCTION OF PUCCA FLOOR, URINE TANK AND FODDER TROUGH FOR CATTLE

Usually, cattle are kept in sheds with kutcha floor. The place where cattle rest often gets messy with cow dung, cattle urine and water. In particular, during rainy seasons the kutcha floor becomes unhealthy for and causes several infectious diseases for the cattle. Also, cattle urine and cow dung are important resources that could enhance soil fertility. If the floor of the cattle shed is constructed as pucca floors with cement and stones, this would enable better collection of dung and cattle urine as well as protect cattle from infections. A tank constructed for urine collection could be used to make liquid manure to enhance soil fertility. A fodder trough would facilitate proper feeding of cattle and minimise waste of fodder.

The area of the cattle shed floor for 6 heads of cattle is 26.95 sq.m. (7.7mx3.5m). For constructing the cattle shed floor in cement concrete, a 1 cum fodder trough (7.7mx0.2mx0.65m) and a cattle urine

collection tank of 250 litres, the cost works out to around Rs. 35,000 per unit. The unskilled labour:material ratio is 30:70.

Selection will be made only from those households eligible under MGNREGA for work on private land.

17. AZOLLA AS CATTLE-FEED SUPPLEMENT

Azolla is an easy to use nutritional supplement for cattle. It is rich in proteins, essential amino acids, vitamins (vitamin A, vitamin B12 and Beta-Carotene), growth promoter intermediaries and minerals like calcium, phosphorous, potassium, iron, copper, magnesium. On a dry weight basis, it contains 25-35 percent protein, 10-15 percent minerals and 7-10 percent of amino acids, bio-active substances and bio-polymers. Livestock can easily digest it, owing to its high protein and low lignin content. Azolla can be mixed with concentrates or can be given directly to livestock. Azolla can also be fed to poultry, sheep, goats, pigs and rabbits.

Azolla can be grown in artificial water bodies made preferably under shade. A pit of the size of 2m x 2m x 0.2 m is dug as a first step. The bottom of the pit is covered with plastic gunnies. About 10-15 kg of sieved fertile soil is uniformly spread over this plastic sheet. Slurry (made of 2 kg cow dung and 30 gm of super phosphate in 10 litres of water) is poured on to this sheet. More water is poured to make the water level reach about 10 cm. About 500 gm-1 kg of fresh and pure culture of Azolla is introduced in the pit. Azolla will rapidly grow and fill the pit within 10 – 15 days. About 500 – 600 gm of Azolla can be harvested daily thereafter.

The cost of one Azolla pit is around Rs.2000. The unskilled labour : material ratio is 15:85. This activity is only for those households eligible under MGNREGA for work on private land.

E. FISHERIES RELATED WORKS

18. FISHERIES IN SEASONAL WATER BODIES ON PUBLIC LAND

Fisheries as a livelihood activity for the poor have immense scope. Many small reservoirs, tanks, water harvesting ponds created under MGNREGA are ideally suited for fish production. In the floodplains of Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal, there are a large number of small water bodies with potential for fisheries development. These water bodies are mainly fed by surface run-off from local catchments. Varying water spread area, pronounced seasonality of filling, high dependence on rainfall and competitive claims on stored water for irrigation are some of the characteristics of these water bodies.

There is a large gap in the potential and actual yields in these rainfed water bodies. There is scope for enhancing the fish production by 3 to 5 times from the current productivity levels. Adopting culture based fisheries with advanced fingerlings (100 mm and above) at stocking rates of 500-1000 fingerlings per ha can substantially increase productivity in the water spread area in small reservoirs, estimated at 1.2 million ha in the country.

The activities involved include digging and landscaping of the bed of the water body to suit fish production, ensuring year round dead-storage, protecting the spill-ways and provision of small fish nursery ponds with assured water for rearing fingerlings. A 500cu.m. fish nursery pond and excavation of 15,000

cum. in an existing tank bed, along with a fish drying platform of 30 sq.m., will cost around Rs. 11 lakhs. The approximate unit cost of this activity is Rs. 75 per cubic metre of excavation and the unskilled labour:material ratio works out to 80:20.

The common pool nature of these water bodies makes fish production in them a complex task. This will need to be tackled through appropriate arrangements at the local level, which may require facilitation, especially in the initial stages.

F. WORKS IN COASTAL AREAS

19. FISH DRYING YARDS

Fish drying yards in coastal areas are concrete surfaces constructed in connection with fish landing centres and fishery harbours for hygienic drying of fish in a traditional way. For this purpose, a yard is constructed on the seashore of 10m x 10m size with 15 cm thick plain cement concrete and brick protection work of 20cm thickness. This yard is covered by a net for protection of fish.

The unit cost of such a fishing yard is about Rs. 75,000. The unskilled labour:material ratio is 15:85.

20. BELT VEGETATION

Vegetation cover such as mangrove, casuarina and palm plantation has the potential to address sea erosion. The cost per unit is about Rs.20. The unskilled labour:material ratio is 80:20.

21. CONSTRUCTION OF STORM WATER DRAINS FOR COASTAL PROTECTION

Constructing a channel parallel to the road and other connecting channels to the main channel at 100m interval at required slope can make a big contribution to coastal protection. The channels are constructed by random rubble masonry. The width of the channel is 0.60 m. Size of rubble work is 0.60cmx0.60cm. The depth of the channel is 0.60cm.

The unit cost of such a 100m long storm water drain is about Rs.2,30,000. The unskilled labour:material ratio is 15:85.

G. RURAL DRINKING WATER RELATED WORKS

22. SOAK PITS

Soak Pit is an underground structure that allows water to soak into the ground. This helps in improving sustainability of the source of water.

The unit cost of this activity is around Rs.2000. The unskilled labour: material ratio is 50:50.

This activity may be taken up under MGNREGA only if the soak pit has not been constructed under NRDWP. All NRDWP specifications will be strictly followed.

This is an activity that can be undertaken both on public land and private land. In the latter case, this activity is only for those households eligible under MGNREGA for work on private land.

23. RECHARGE PITS (FOR POINT RECHARGE)

A Recharge Pit allows rainwater to replenish groundwater. It can be built to recharge a borewell or just to help the water infiltration in an area. This helps in improving sustainability of the source of water.

The unit cost of this activity is around Rs.5000. The unskilled labour: material ratio is 50:50.

This activity may be taken up under MGNREGA only if the recharge pit has not been constructed under NRDWP. All NRDWP specifications will be strictly followed.

This is an activity that can be undertaken both on public land and private land. In the latter case, this activity is only for those households eligible under MGNREGA for work on private land.

Full technical details of the works in this section are available with the Ministry of Drinking Water Supply and Sanitation, Government of India

H. RURAL SANITATION RELATED WORKS

24. INDIVIDUAL HOUSEHOLD LATRINES (IHHL)

The unit cost of this work is Rs.9900. Under the Total Sanitation Campaign (TSC), the Government contribution is Rs.4500 and the beneficiary contribution is Rs. 900.

A total of upto 20 persondays of unskilled labour and 6 persondays of skilled labour may be taken up under MGNREGA. However, the contribution from MGNREGA would not exceed Rs. 4,500 per beneficiary. The unskilled labour:material ratio of the MGNREGA contribution will be 60:40. The MGNREGA material component will be used only for the skilled labour component of the total cost of IHHL.

Skilled labour and mate provided will be under the material cost and should not exceed 40% of the total cost under MGNREGA

Selection will be made only from those households, which are eligible under MGNREGA for work on private land and who have not yet been covered for IHHLs under the Total Sanitation Campaign (TSC).

All TSC specifications will be strictly followed. Creating awareness for this work is a key to success. The IEC may be done through the resources available with the Ministry of Drinking Water Supply and Sanitation and corresponding State departments.

Detailed Guidelines for this work are Annexed.

25. SCHOOL TOILET UNITS

The unit cost of this activity is Rs.35,000. The unskilled labour:material ratio is 10:90.

This activity may be taken up under MGNREGA only if the school toilet unit has not yet been constructed under TSC. All TSC specifications will be strictly followed.

Creating awareness for this work is a key to success. The IEC may be done through the resources available with the Ministry of Drinking Water Supply and Sanitation and corresponding State departments.

26. ANGANWADI TOILETS

The unit cost of this activity is Rs.8,000. The unskilled labour:material ratio is 17:83.

This activity may be taken up under MGNREGA only if the anganwadi toilet unit has not yet been constructed under TSC. All TSC specifications will be strictly followed.

Creating awareness for this work is a key to success. The IEC may be done through the resources available with the Ministry of Drinking Water Supply and Sanitation and corresponding State departments.

27. SOLID AND LIQUID WASTE MANAGEMENT (SLWM)

Effective solid and liquid waste management leads to multiple benefits:

Health benefits from safe disposal of waste that would otherwise contaminate the environment.

Economic benefits through re-use/recycling of products that would have been discarded as waste.

Aesthetic benefits from a clean environment without unsightly mounds of rotten waste dumped in the open.

Effective management of SLWM includes management of biodegradable and non biodegradable waste, management of all grey water generated in the village and general cleanliness of the village. The activities under SLWM include:

I. Solid Waste Management

- (i) Construction of Compost pits/common compost pits,
- (ii) System for collection, transportation, segregation and composting and disposal of household garbage.

II. Liquid Waste Management

- (i) Construction of low cost drainage,
- (ii) Construction of soakage channels/ pits, reuse of waste water,
- (iii) Construction of stabilization ponds.

A typical SLWM project for a population of 1000 people comes to around Rs.5 lakhs. The unskilled labour:material cost ratio is 35:65. Under MGNREGA, only proposed or completed Nirmal Grams will be eligible for this activity. All TSC specifications will be strictly followed.

Creating awareness for this challenging work is the key to success. This IEC may be done through the resources available with the Ministry of Drinking Water Supply and Sanitation and corresponding State departments.

Full technical details of the works in this section are available with the Ministry of Drinking Water Supply and Sanitation, Government of India

I. FLOOD MANAGEMENT RELATED WORKS

28. DEEPENING AND REPAIR OF FLOOD CHANNELS

A major shift in the 12th Plan strategy of flood management is the renewed focus on reviving local drainages. In many flood-prone villages, drainages are in a state of disrepair or have become silted up or have been encroached upon. These channels play a crucial role in directing flood waters out of the village. Both field channels (connecting farms to the main channel) and the main channel(s) of the village need to be repaired and deepened.

The unit cost of deepening the main channels is around Rs.180 per metre. The unskilled labour: material ratio is 100:0

The unit cost of deepening the field channels is around Rs.30 per metre. The unskilled labour:material ratio is 100:0

29. CHAUR RENOVATION

Waterlogged lowlands, known as chaur in Bihar, are the natural, saucer-shaped, topographically low-lying areas where rainwater accumulates. They can play a major role in flood mitigation because they act as natural "sponges" for flood waters. The surface area of a chaur can be very large, covering portions of several villages. Renovated chaur could be used as multi-purpose farm ponds. The mud excavated from the chaur can be raised on the side as embankments on which crops like banana, papaya, mango, pigeon pea and cashew nut can be grown. The pond water can be used to irrigate the non-waterlogged, upland area. Experiments have shown that in waterlogged areas, cultivation of water chestnut (*Trapa bispinosa*) can be quite profitable.

The unit cost of chaur renovation is around Rs. 4.7 lakhs per hectare. The unskilled labour:material ratio is 100:0

J. IRRIGATION COMMAND RELATED WORKS

30. REHABILITATION OF MINORS, SUB-MINORS AND FIELD CHANNELS

Surface irrigation systems have made a major contribution towards promoting food security and reduction of poverty in India. However, a major challenge facing surface irrigation systems is the growing gap between irrigation capacity created and irrigation capacity utilised. The major reason for this growing gap is the neglect of command area development, especially field channels.

The works permissible under MGNREGA will entail one-time rehabilitation of minors, sub-minors and field channels, including desilting, repair of minor cracks, earth leveling, repair of earthen embankments, bank raising and resurfacing canal base with clay. Regular O&M will not be a permissible activity under MGNREGA.

The unit cost of this activity is Rs.3000 per hectare. The labour: material ratio is 60:40


(D.K. Jain)

Joint Secretary (MGNREGA)

SCHEDULE I

[See section 4 (3)]

MINIMUM FEATURE OF A RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME

¹[***]

²[1. The Scheme notified under section 4 by all States shall be called 'the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme' and all documents pertaining to the said Scheme shall have a mention of 'the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005)'.]

²[1A. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme shall hereinafter be referred to as "Mahatma Gandhi NREGS" and any reference in the said scheme to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 shall be referred to as "Mahatma Gandhi NREGA".]

³[1B. The focus of the Scheme shall be on the following works and the order of priority shall be determined by each Gram Panchayat in meetings of the Gram Sabha and the Ward Sabha, namely:-

- (i) water conservation and water harvesting including contour trenches, contour bunds, boulder checks, gabion structures, underground dykes, earthen dams, stop dams and springshed development;
- (ii) drought proofing including afforestation and tree plantation;
- (iii) irrigation canals including micro and minor irrigation works;
- (iv) provision of irrigation facility, dug out farm pond, horticulture, plantation, farm bunding and land development on land owned by households specified in paragraph 1C;
- (v) renovation of traditional water bodies including desilting of tanks;
- (vi) land development;

¹ Paragraph 1A omitted by S.O. 1860(E), dated 30th July, 2010. Earlier paragraph 1A was inserted by S.O. 323(E), dated 6th March, 2007 (w.e.f. 6-3-2007).

² Ins. by S.O. 1860(E), dated 30th July, 2010.

³ Subs. by S.O. 1022(E), dated 4th May, 2012, for paragraph 1B. Earlier Paragraph 1 renumbered as paragraph 1B thereof, by S.O. 1860(E), dated 30th July, 2010. Earlier sub-paragraph (iv) subs, by S.O. 2202 (E), dated 22nd September, 2011, S.O. 1824 (E), dated 22nd July, 2009 and S.O. 323(E), dated 6th March, 2007.

- (vii) flood control and protection works including drainage in water logged areas including deepening and repairing of flood channels, chaur renovation, construction of storm water drains for coastal protection;
- (viii) rural connectivity to provide all weather access, including culverts and roads within a village, wherever necessary;
- (ix) construction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra as Knowledge Resource Centre at the Block level and as Gram Panchayat Bhawan at the Gram Panchayat level;
- (x) agriculture related works, such as, NADEP composting, vermi-composting, liquid bio-manures;
- (xi) livestock related works, such as, poultry shelter, goat shelter, construction of pucca floor, urine tank and fodder trough for cattle, azolla as cattle-feed supplement;
- (xii) fisheries related works, such as, fisheries in seasonal water bodies on public land;
- (xiii) works in coastal areas, such as, fish drying yards, belt vegetation;
- (xiv) rural drinking water related works, such as, soak pits, recharge pits;
- (xv) rural sanitation related works, such as, individual household latrines, school toilet units, anganwadi toilets, solid and liquid waste management;
- (xvi) any other work which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government.]

⁴[IC. All activities mentioned in items (iv), (x), (xi) and items (xiii) to (xv) of paragraph 1B shall be allowed on land or homestead owned by households belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes or below poverty line families or the beneficiaries of land reforms or the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India or that of the small or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008, or the beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007).

1D. The works referred to in items (iv), (x), (xi) and items (xiii) to (xv) of paragraph 1B shall be taken up subject to the following conditions, namely:-

⁴ Ins. by S.O. 1022(E), 4th May, 2012.

- a. the households referred to in paragraph 1C shall have the job card; and
- b. the beneficiaries shall work on the project undertaken on their land or homestead.]

2. Creation of durable assets and strengthening the livelihood resources base of the rural poor shall be an important objective of the Scheme.

⁵[3. The works taken up under the scheme shall be in rural areas and shall be subject to the following-

- a. A unique identity number shall be given to each work.
- b. All work must be executed by the workers who have job cards and who have demanded work.
- c. No Person below the age of 18 shall be permitted to work under MGNREGA Projects.
- ⁶[d. Each muster roll shall have a unique identity number and be certified by the Programme Officer and shall contain such mandatory information as may be specified by order, by the Central Government.]
- e. Muster Rolls duly signed by programme Officer and properly numbered shall be maintained on the worksite. Any muster roll not signed by the Programme Officer and properly numbered will be treated as un-authorized and shall not be maintained at the worksite.
- f. The workers will countersign their attendance and the amount of wages earned of the Muster Roll at the worksite.
- ⁷[g. A detailed record of muster rolls will be maintained in the registers as prescribed by the Central Government from time to time.]
- h. When a work is in progress, the workers engaged in that work will select from among themselves not less than five workers on a weekly

⁵ Subs. by S.O. 3000(E), dated 31st December, 2008, for paragraph 3.

⁶ Subs. by S.O. 1022(E) dated 4th May, 2012, in paragraph 3 for sub-paragraph (d).

⁷ Subs. the words, Government of India" with "Central Government, wherever they occur, by S.O. 1022(E) dated 4th May, 2012.

rotational basis to verify and certify all the bills/vouchers of their worksite at least once a week.

- i. A copy of the sanction work order must be available for public inspection at the worksite.
- j. Measurement of work will be recorded in the Measurement Books maintained by qualified technical personnel in charge of the worksite.
- k. Measurement records of each work and worker must be available for public inspection.
- l. A Citizen's Information Board must be put up at every worksite and updated regularly in the manner prescribed by the Central Government.
- m. Any person must be able to access muster rolls on demand on the worksite all days during all working hours.
- n. The vigilance and Monitoring Committee setup according to the instructions of the Central Government will check all works and its evaluation report will be recorded in the Works Register in the format prescribed by the Central Government and be submitted to the Gram Sabha during Social Audit.]

⁸[***].

⁹[5. As part of the Scheme, the State Government shall provide for proper maintenance of the public assets created under the Scheme.]

¹⁰[***].

¹¹[7. The State Government shall link the wages with the quantity of work and it shall be paid according to the schedule of rates fixed by the State Government for different types of work every year, in consultation with the State Council.]

⁸ Paragraph 4 omitted by S.O. 1022(E), dated 4th May, 2012.

⁹ Subs. by S.O. 1022(E), dated 4th May, 2012, for paragraph 5.

¹⁰ Paragraph 6 omitted by S.O. 1022(E), dated 4th May, 2012.

¹¹ Subs. by S.O. 1022(E), dated 4th May, 2012, for paragraph 7.

¹²[8. (1) The schedule of rates of wages for various unskilled labourers shall be so fixed up that an adult person working for nine hours including an hour of rest would normally earn a wage equal to the wage rate.

(2) The working days of an adult worker shall be so arranged that inclusive of intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.]

¹³[8A. The average out-turn of work put out by men and workers working in a group will be the basis for fixing task based schedule of rates so that there is no gender based discrimination in the Schedule of Rates.]

¹⁴[9. The cost of material component of projects including the wages of the skilled and semi-skilled workers taken up under the scheme shall not exceed forty per cent. of the total project costs at the level of each Gram Panchayat.]

10. It shall be open to the programme officer and Gram Panchayat to direct any person who applied for employment under the Scheme to do work of any type permissible under it.

11. The scheme shall not permit engaging any contractor for implementation of the projects under it.

12. As far as practicable, a task funded under the scheme shall be performed by using manual labour and not machines.

¹⁵[13. Every scheme shall contain adequate provisions for ensuring transparency and accountability at all levels of implementation as stated below:

a. Proactive Disclosure

- (i) At worksite proactive disclosure shall be through display of information through Citizen information Boards, reading out of muster rolls information regarding attendance, work done and wages paid in the presence of workers at the end of the day by the person authorized. The measurements in the

¹² Subs. by S.O. 1022(E), dated 4th May, 2012. Earlier Subs. by S.O. 88(E), dated 14th January, 2008, for paragraph 8.

¹³ Ins. By S.O. 88(E), dated 14th January, 2008.

¹⁴ Subs. by S.O. 1022(E), dated 4th May, 2012, for paragraph 9.

¹⁵ Subs. By S.O. 3000(E), dated 31st December, 2008, for paragraph 13.

Measurement Book will also be read out during the measurement of works before the workers.

(ii) At the Gram Panchayat and Block Programme Office proactive disclosure shall be through display of information on boards and shall include at least information pertaining to provision of employment, funds received and expenditure, shelf of projects approved.

(iii) All information on MGNREGA will be placed in public domain through the website for MGNREGA as prescribed by the Central Government and be available through free downloadable electronic form.]

¹⁶[***]

14. Provisions for regular inspection and supervision of works taken up under the scheme shall be made to ensure proper quality of work as well as to ensure that the total wages paid for the completion of the work is commensurate with the quality and quantity of work done.

15. The District Programme Coordinator, the programme officer and the Gram Panchayat implementation the scheme shall prepare annually a report containing the facts and figures and achievements relating to the implementation of the scheme within his or its jurisdiction and a copy of the same shall be made available to the public on demand on payment of such fee as may be specified in the Scheme.

¹⁷[16. All accounts and records relating to the scheme shall be made available for public security free of cost. Any person desirous of obtaining a copy or relevant extracts therefrom may be provided such copies or extracts on demand not later than three working days from the time of application and after paying such fee as may be specified in the Scheme.]

17. A copy of the muster roll of each Scheme or project under a scheme shall be made available in the office of the Gram Panchayat and the Programme Officer for inspection by any person interested after paying such fee as may be specified in the Scheme.

¹⁶ Sub-paragraph (b) omitted by S.O. 1484(E), dated 30th June, 2011.

¹⁷ Subs. by S.O. 3000(E), dated 31st December, 2008, for paragraph 16.

SCHEDULE II

(See Section 5)

CONDITIONS FOR GURANTEED RURAL EMPLOYMENT UNDER A SCHEME AND MINIMUM ENTITLEMENTS OF LABOURERES

1. The adult member of every household who-

- a. reside in any rural areas; and
- b. are willing to do unskilled manual work,

may submit their names, age and the address of the household to the Gram Panchayat at the village level (hereafter in this Schedule referred to as the Gram Panchayat) in the jurisdiction of which they reside for registration of their household for issuance of a job card.

¹⁸[2. (1) It shall be the duty of the Gram Panchayat to register the household, after making such enquiry as it deems fit and issue a job card containing the following essential details of registered adult members of the household, namely

- i. Job card number;
- ii. household member-wise work demand and allocation;
- iii. description of the work done
- iv. dates and days worked;
- v. muster roll numbers by which wages have been paid
- vi. amount of wages paid;
- vii. unemployment allowance, if any paid;
- viii. postal account/bank account number
- ix. insurance policy number; and
- x. elector's photo identity card number voters identity, if any.
- ¹⁹[xi. Aadhaar number, if issued]

¹⁸ Subs. By S.O. 802(E), dated 2nd April, 2008, for paragraph 2.

¹⁹ Ins. by S.O. 1022(E), dated 4th May, 2012, for paragraph 2.

(2) All entries in the Job Card shall be duly authenticated by signature of an authorised officer.

(3) The Job Cards issued under sub-paragraph (1) shall bear the photographs of only the registered adult members of the households to whom that Job Card has been issued.

(4) No photograph, names or details of any person other than that of the registered adult members of the household to whom that Job Card belongs shall be affixed or recorded in the Job Card.

(5) All Job Cards shall be in the custody of the Job Card holders to whom they belong.]

3. The registration made under paragraph 2 shall be for such period as may be laid in the Scheme, but in any case not less than five years, and may be renewed from time to time.

4. Every adult member of a registered household whose name appears in the job card shall be entitled to apply for unskilled manual work under the Scheme.

5. All registered persons belonging to a household shall be entitled to employment in accordance with the Scheme made under the provisions of this Act, for as many days as each applicant may request, subject to a maximum of one hundred days per household in a given financial year.

6. The Programme Officer shall ensure that every applicant referred to in paragraph 5 shall be provided unskilled manual work in accordance with the provisions of the Scheme within fifteen days of receipt of an application or from the date he seeks work in case of advance application, whichever is later:

Provided that priority shall be given to women in such a way that at least one third of the beneficiaries shall be women who have registered and requested for work under this Act.

²⁰[7. Applications for work must be for at least fourteen days of continuous work, other than the works relating to access to sanitation facilities, for which application for work must be for at least six days continuous work.]

²⁰ Subs by S.O. 2266(E), dated 30th September, 2011 for paragraph 7.

8. There shall be no limit on the number of days of employment for which a person may apply, or on the number of days of employment actually provided to him subject to the aggregate entitlement of the household.

9. Applications for work may be submitted in writing either to the Gram Panchayat or to the Programme Officer, as may be specified in the Scheme.

10. The Gram Panchayat and Programme Officer, as the case may be, shall be bound to accept valid applications and to issue a dated receipt to the applicant. Group applications may also be submitted.

11. Applicants who are provided with work shall be so intimated in writing, by means of a letter sent to him at the address given in the job card and by a public notice displayed at the office of the Panchayats at district, intermediate or village level.

12. As far as possible, employment shall be provided within a radius of five kilometres of the village where the applicant reside at the time of applying.

²¹13. A new work under the scheme can be commenced if at least ten labourers become available for work;]

Provided that this condition shall not be applicable for new works, as determined by the State Government, in hilly areas and in respect of afforestation.

²²[14. In case the employment is provided outside the radius specified in paragraph 12, it must be provided within the Block, and the labourers shall be paid ten per cent., of the wage rate as extra wages to meet additional transportation and living expenses.]

²³[15. A period of employment shall be at least continuous fourteen days with not more than six days in a week.]

16. In all cases where unemployment allowance is paid, or due to be paid, the Programme Officer shall inform the District Programme Coordinator in writing the reasons why it was not possible for him to provide employment or cause to provide employment to the applicants.

²¹ Subs. by S.O. 324(E), dated 6th March, 2007, for paragraph 13 (w.e.f. 6-3-2007).

²² Subs. by S.O. 1022(E), dated 4th May, 2012, for paragraph 14.

²³ Subs. by S.O. 1022(E), dated 4th May, 2012, for paragraph 15.

17. The District Programme Coordinator shall, in his Annual Report to the State Council **explain** as to why employment could not be provided in cases where payment of unemployment allowances is involved.

18. Provision shall be made in the Scheme for advance applications, that is, application **which** may be submitted in advance of the date from which employment is sought.

19. Provision shall be made in the Scheme for submission of multiple applications by the **same** person provided that the corresponding periods for which employment is sought do not overlap.

20. The Gram Panchayat shall prepare and maintain or cause to be prepared and **maintained** such registers, vouchers and other documents in such form and in such manner as **may** be specified in the Scheme containing particulars of job cards and pass books issued, name, **age** and address of the head of the household and the adult members of the household registered **with** the Gram Panchayat.

21. The Gram Panchayat shall send such list or lists of the names and addresses of **households** and their adult members registered with it and supply such other information to the **concerned** Programme Officer at such periods and in such form as may be specified in the **Scheme**.

22. A list of persons who are provided with the work shall be displayed on the notice board **of** the Gram Panchayat and at the office of the Programme Officer and at such other place as the Programme Officer may deem necessary and the list shall be open for inspection by the State Government and any person interested.

23. If the Gram Panchayat is satisfied at any time that a person has registered with it by **furnishing** false information, it may direct the Programme Officer to direct his name to be struck **off** from the register and direct the applicant to return the job card:

Provided that no such action under this paragraph shall be directed unless the applicant **has** been given an opportunity of being heard in the presence of two independent persons.

24. If any personal injury is caused to any person employed under the Scheme by accident **arising** out of and in the course of his employment, he shall be entitled to free of charge, such **medical** treatment as is admissible under the Scheme.

25. Where hospitalization of the injured worker is necessary, that State Government shall arrange for such hospitalization including accommodation, treatment, medicines and payment of daily allowance not less than half of the wage rate required to be paid had the injured been engaged in the work.

26. If a person employed under a Scheme dies or becomes permanently disabled by accident arising out of and in the course of employment, he shall be paid by the implementing agency an *ex gratia* payment at the rate of twenty-five thousand rupees or such amount as may be notified by the Central Government, and the amount shall be paid to the legal heirs of the deceased or the disable, as the case may be.

27. The facilities of safe drinking water, shade for children and periods of rest, first aid box with adequate material for emergency treatment for minor injuries and other health hazards connected with the work being performed shall be provided at the work site.

28. In case the number of children below the age of six years accompanying the women working at any site are five or more, provisions shall be made to depute one of such women worker to look after such children.

29. The person deputed under paragraph 28 shall be paid wage rate.

30. In case the payment wages is not made within the period specified under the Scheme, the labourers shall be entitled to receive payment of compensation as per the provisions of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936).

²⁴[31. The payment of wages shall unless so exempted be made through the individual or joint savings accounts of the workers in the banks or post offices opened in accordance with the directions of the Central Government unless so exempted.]

²⁵[***]

²⁴ Subs. by S.O. 1022(E), dated 4th May, 2012, for paragraph 14. Earlier, subs. by S.O. dated 513(E), dated 19th February, 2009.

²⁵ Paragraph 32 omitted by S.O. 513(E), dated 19th February, 2009.

33. If any personal injury is caused by accident to a child accompanying person who is employed under a Scheme, such person shall be entitled to, free of charge, such medical treatment for the child as may be specified in Scheme and in case of death or disablement, through an *ex gratia* payment as may be determined by the State Government

34. In case of every employment under the Scheme, there shall be no discrimination solely on the ground of gender and the provisions of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), shall be complied with.

²⁶[35. (1) Notwithstanding anything contained in paragraphs 1,3,9 and 14 of Schedule II Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2009), in the event of national calamities in the nature of flood, cyclone, tsunami and earthquake resulting into mass dislocation of rural population the adult members of rural households of areas so affected may-

- (i) seek for registration and get job card issued by Gram Panchayat or Programme Officer of the area of temporary relocation;
- (ii) submit written or oral applications for work to the Programme Officer or the Gram Panchayat of the area of temporary relocation; and
- (iii) apply for re-registration and re-issuance of job card in the event of loss or destruction.

(2) In the event of restoration of normalcy, the job card so issued shall be re-endorsed at original place of habitation and shall be clubbed with original job card on being retrieved.

(3) The number of days of employment so provided shall be counted while computing 100 days of guaranteed employment per household.]

²⁷[36. The complaints received, taken cognizance of *suo motu* and as otherwise provided under the Act or Schedule therein shall be dealt as prescribed below:

²⁶ Added by S.O. 2188(E), dated 11th September, 2008.

²⁷ Added by S.O. 2999(E), dated 31st December, 2008.

- a) The Programme Officer shall enter every complaint in a complaint register maintained by him and dated and numbered acknowledgement shall be issued.
- b) Enquiry through spot verification, inspection and disposal shall be completed within 7 working days
- c) Complaints that fall within the jurisdiction of the Programme Officer, including any complaints concerning the implementation of the Act by a Gram Panchayat shall be disposed of by the Programme Officer within 7 days, as prescribed under section 23(6) of the Act. In case a complaint relates to a matter to be resolved by any other authority, the Programme Officer shall conduct a preliminary enquiry and refer the matter to such authority within 7 days under intimation to the complainant.
- d) Failure to dispose of a complaint in 7 days will be considered a contravention of the Act by the Programme Officer, punishable under section 25. Complaints against such failure will be lodged with the District Programme Coordinator.
- e) In case of a *prime facie* evidence regarding financial irregularities the District Programme Coordinator will ensure that a First Information Report is filed.
- f) State Government/District Programme Coordinator/Programme Officer or any other authority authorized by the State Government may inquire into any complaint on its own will or through reference and establishment of guilt will impose the penalty against the concerned guilty under section 25 of the Act.
- g) In case the concerned authority finds violation of entitlements, it will be responsible for informing and redressing the person/party aggrieved. The concerned authority will be responsible for such grievance redressal with a week and not after than 15 days.
- h) The action taken shall be informed to the complainant and disclosed in two vernacular newspapers in prescribed format once a quarter.

- i) The action taken on the complaints received by the Programme Officer and the District Programme Coordinator shall be placed before the meetings of the intermediate Panchayat and the District Panchayat respectively.
- j) Appeals against the orders of the Gram Panchayat shall be made to the Programme Officer; those against the orders of the Programme Officer shall be made to District Programme Coordinator; those against the District Programme Coordinator shall be made to State Commissioner (NREGS), Divisional Commissioner (NREGS) and State Grievance Redressal Officer.
- k) All Appeals shall be made within 45 days of the order issued.
- l) All Appeals shall be disposed off within one month.

अनुसूची 1

[धारा 4 (3) देखिए]

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं

1[****]¹

²1. धारा 4 के अधीन सभी राज्यों द्वारा, अधिसूचित स्कीम का संक्षिप्त नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम' होगा और उक्त स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42)' का उल्लेख होगा।

²1क. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को, इसमें इसके पश्चात् 'महात्मा गांधी एनआरईजीएस' कहा जाएगा और स्कीम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रति किसी संदर्भ को 'महात्मा गांधी नरेगा' कहा जाएगा।

³ 1ख. स्कीम के केन्द्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों पर होगा और उसकी पूर्विक्ता क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभा के अधिवेशनों में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय, जिसके अंतर्गत कन्दूर खाइयां, कन्दूर बंध, गोलशम चेक, गबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास भी हैं;

(ii) सूखारोधी, जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी है;

(iii) सिंचाई नहरें, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं;

(iv) पैरा 1ग में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढबंधन और भूमि विकास का उपबंध;

(v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है;

(vi) भूमि विकास;

(vii) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का संनिर्माण;

(viii) सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़कें भी हैं;

¹ पैरा 1क का का0आ0 1860(अ), तारीख 30 जुलाई, 2010 द्वारा लोप किया गया। इसके पहले का0आ0 323(अ) तारीख 06 मार्च, 2007 को पैरा 1क अंतःस्थापित किया गया था (6-3-2007 से)।

² का0आ0 1860(अ), तारीख 30 जुलाई, 2010 द्वारा अंतःस्थापित किया गया

³ का0आ0 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 को पैरा 1ख के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया। इससे पहले, का0आ0 1860(अ) तारीख 30 जुलाई, 2010 द्वारा पैरा 1 को पैरा 1ख के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया। पहले के पैरा के उप-पैरा को का0आ0(अ) 2202(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2011, का0आ0 1824(अ) तारीख 22 जुलाई, 2009 तथा का0आ0 323(अ), 06 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था।

- (ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण;
- (x) एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्विड बायो-मेन्चोर जैसे कृषि संबंधी संकर्म;
- (xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म;
- (xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबंधी संकर्म;
- (xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म;
- (xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म;
- (xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनबाड़ी शौचालय, टोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म;
- (xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचित किया जाए¹;

¹ग. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमांत कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह संपदा पर अनुज्ञात किए जाएंगे।

¹घ. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में निर्दिष्ट संकर्मों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) पैरा 1ग में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा; और
- (ख) हिताधिकारी, उनकी भूमि या गृह संपदा पर की जाने वाली परियोजना पर कार्य करेंगे।
2. टिकारू आस्तियों का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करना स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा।
3. स्कीम के अधीन किए गए कार्य ग्रामीण क्षेत्र में होंगे और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होंगे, अर्थात् :-
- (क) प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष पहचान सं. दी जाएगी;

¹ 1ग. और 1घ को का0आ0 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा अंतःस्थापित किया गया,

² का0आ0 3000 (अ), तारीख 31 दिसम्बर 2008 द्वारा पैरा 3 के स्थान पर रखा गया,

- (ख) सभी कार्य ऐसे कर्मकारों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिनके पास जॉबकार्ड है और जिन्होंने कार्य की मांग की है;
- (ग) 18 वर्ष से कम की आयु के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम परियोजनाओं के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;
- ⁶(घ) प्रत्येक मस्टर रोल की विशिष्ट पहचान संख्या होगी और उसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उसमें ऐसी अनिवार्य जानकारी अंतर्विष्ट होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए;
- (ङ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और समुचित रूप से संख्यांकित मस्टर रोल कार्य स्थल पर रखी जाएगी और ऐसी मस्टर रोल जो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और समुचित रूप से संख्यांकित नहीं है, उसे अप्राधिकृत समझा जाएगा और कार्य स्थल पर नहीं रखी जाएगी;
- (च) कर्मकार अपनी उपस्थिति और कार्य स्थल पर मस्टर रोल में उपाजित मजदूरी की रकम को प्रति हस्ताक्षरित करेंगे;
- ⁷(छ) समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित मस्टर रोलों के विस्तृत अभिलेख रजिस्ट्रों में रखे जाएंगे;
- (ज) जब कार्य प्रगति पर है, कर्मकार उस कार्य में लगे हैं सप्ताह में कम से कम एक बार उनके कार्य स्थल के सभी बिलों और वाउचरों का सत्यापन और प्रमाणन करने के लिए साप्ताहिक चक्रानुक्रम के आधार पर उनमें से कम से कम पांच कर्मकारों का चयन किया जाएगा;
- (झ) अनुमोदन या कार्य आदेश की एक प्रति कार्य स्थल पर सार्वजनिक के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी;
- (ञ) कार्य का मापमान कार्य स्थल के भास्साघक अर्हित तकनीकी कर्मिक द्वारा रखी गई मापमान पुस्तकों में अभिलिखित किया जाएगा;
- (ट) प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कर्मकार के मापमान अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे;
- ⁷(ठ) प्रत्येक कार्य स्थल पर एक नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए;
- (ड.) कोई व्यक्ति सभी कार्य घंटों के दौरान कार्य स्थल पर मांग किए जाने पर मस्टर रोलों के प्रति पहुँच रखने के लिए योग्य होगा; और

⁶ का0आ10 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा पैरा 3 में उप-पैरा (घ) के स्थान पर रखा गया,

⁷ का0आ10 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा संशोधित किया गया इसके अनुसार 'भारत सत्कार' शब्द के स्थान पर 'जहाँ जहाँ वे जाते हैं' केन्द्र सत्कार' शब्द रखा जाएगा।

⁷(ब) केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार स्थापित की गई सतर्कता और मानीटरी समिति सभी कार्यों और उस पर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच करेगी जो भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में कार्य रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी;

[****]⁸

5. ⁸राज्य सरकार, स्कीम के भाग के रूप में, स्कीम के अधीन सृजित लोक आस्तियों के उचित रखरखाव की व्यवस्था करेगी।

[****]¹⁰

7 ¹¹राज्य सरकार मजदूरी को कार्य की मात्रा से संबद्ध करेगी और राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार संदत्त की जाएगी।

8 ¹²(1) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि विश्राम के एक घंटे सहित नौ घंटे के लिए काम करने वाला कोई व्यस्क व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके।¹³

(2) किसी व्यस्क कर्मकार के कार्यदिवस, जिसके अंतर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस को बारह घंटे से अधिक न हों¹⁴;

¹³8 - क किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किए गए औसत कार्य आधारित दरों की सूची नियत करने के लिए आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लिंग आधारित कोई विभेद न हो।¹⁴

9. ¹⁴कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की सामग्री संघटक की लागत, जिसके अंतर्गत कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

10. कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन करता है, यह निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रकार का कार्य करे।

11. स्कीम में उसके अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी ठेकेदार को लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

12. यथाव्यवहार्य, स्कीम के अधीन वित्त पोषित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके पूरा किया जाएगा, मशीन का नहीं।

⁸ का0आ0 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा पैरा 4 का लोप किया गया,

⁹ का0आ0 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा पैरा 5 के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया,

¹⁰ का0आ0 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा पैरा 8 का लोप किया गया,

¹¹ का0आ0 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा पैरा 7 के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया,

¹² का0आ0 1022 (अ), तारीख 4 मई 2012 द्वारा संशोधित किया गया, इसके पहले का0आ0 88 (अ), तारीख 14 जनवरी, 2008 द्वारा पैरा 8 के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया था,

¹³ का0आ0 88 (अ), तारीख 14 जनवरी, 2008 द्वारा अंतःस्थापित किया गया,

¹⁴ का0आ0 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा पैरा 9 के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया,

13. ¹⁵प्रत्येक स्कीम में कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित रीति में पर्याप्त उपबंध होंगे :

(क) पूर्व सक्रिय प्रकटन:

- (i) प्रत्येक कार्य स्थल पर पूर्व सक्रिय प्रकटन नागरिकता सूचना बोर्ड के माध्यम से, उपस्थिति के संबंध में मस्टर रोल जानकारी का, पढ़े जाना प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्यदिवस के अंत में कर्मकारों की उपस्थिति में किया गया कार्य और संदत्त मजदूरी के माध्यम से किया जाएगा मापन पुस्तक में मापमान कर्मकारों के समक्ष कार्य के मापमान के दौरान पढ़ा जाएगा;
- (ii) ग्राम पंचायत और ब्लॉक कार्यक्रम कार्यालय पर पूर्व सक्रिय प्रकटन बोर्डों पर जानकारी के संप्रदर्शन के माध्यम से किया जाएगा और इसके अंतर्गत नियोजन के उपबंधों से संबंधित जानकारी, प्राप्त निधियां और व्यय अनुमोदित परियोजनाओं के शेल्फ होंगे; और
- (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में कोई जानकारी जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वेबसाइट के माध्यम से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए तथा निःशुल्क डाउनलोड की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी;

18[****]

14. किसी स्कीम के अधीन किए जा रहे संकर्म का, कार्य की उचित क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए और साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य के पूरा किए जाने के लिए संदत्त मजदूरी, किए गए कार्य क्वालिटी और मात्रा के अनुरूप है, नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए उपबंध किए जाएंगे।

15. स्कीम को कार्यान्वित करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत, अपनी अधिकारिता के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों और आकड़ों तथा उपलब्धियों सहित वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति, जनता की मांग पर और ऐसी फीस के संदाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

16. ¹⁷स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रति या इससे संबद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्कीम में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

17. प्रत्येक स्कीम या किसी स्कीम के अधीन परियोजना के मस्टर रोल की एक प्रति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस का संदाय करने के पश्चात, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

¹⁵ का0आ0 3000(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2008 द्वारा पैरा 13 के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया,

¹⁶ का0आ0 1484 (अ), तारीख 30 जून, 2011 द्वारा उप-पैरा (ख) का लोप किया गया,

¹⁷ का0आ0 3000(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2008 द्वारा पैरा 16 के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया,

अनुसूची 2

(धारा 5 देखिए)

किसी स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए शर्तें और
श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियां

1. प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य, जो —

- (i) किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और
- (ii) अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं;

उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात् ग्राम पंचायत कहा गया है) को, जिसकी अधिकारिता में वे निवास करते हैं, अपने नाम, आयु और गृहस्थी के पते, कार्य कार्ड जारी करने के लिए अपनी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. ¹⁸(1) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, गृहस्थी को रजिस्टर करे और गृहस्थी के रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के निम्नलिखित आवश्यक ब्यौरों वाला एक कार्य कार्ड जारी करें, अर्थात् : —

- (i) कार्य कार्ड संख्या;
- (ii) गृहस्थी के सदस्य-वार कार्य की मांग और आबंटन;
- (iii) किए गए कार्य का वर्णन;
- (iv) कार्य करने की तारीखें और दिन;
- (v) उस मस्टर रोल का संख्यांक, जिसके द्वारा मजदूरी संदत्त की गई;
- (vi) संदत्त मजदूरी की रकम;
- (vii) बेकारी भत्ता, यदि कोई संदत्त किया गया हो;
- (viii) डाक महसूल लेखा/बैंक खाता संख्या;
- (ix) बीमा पालिसी संख्या; और
- (x) मतदाता फोटो पहचान पत्र मतदाता पहचान पत्र, यदि कोई हो संख्या ।
- (xi) ¹⁹आधार संख्या, यदि जारी की गई हो,

(2) कार्य कार्ड पर सभी प्रविष्टियां प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से सम्यक रूप से अधिप्रमाणित होंगी।

(3) उप पैरा (1) के अधीन जारी कार्ड पर गृहस्थी के केवल उन्हीं रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के फोटो होंगे, जिनको कार्य कार्ड जारी किया गया है ।

(4) गृहस्थी के ऐसे रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों, जिनका वह कार्य कार्ड हो, से भिन्न किसी व्यक्ति का फोटो, नाम या ब्यौरे कार्य कार्ड पर चिपकाए या अभिलिखित नहीं किए जाएंगे ।

(5) सभी कार्य कार्ड उन कार्य कार्डधारकों की अभिरक्षा में रहेंगे, जिनके वे हैं ।

¹⁸ का0आ0 802 (अ), तारीख 02 अप्रैल, 2008 द्वारा पैरा 2 के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया,

¹⁹ का0आ0 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा पैरा 2 के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया.

3. पैरा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण ऐसी अवधि के लिए जो स्कीम में अधिकथित की जाए किन्तु किसी भी मामले में पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किया जाएगा और इसे समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा।
4. रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक व्यस्क सदस्य, जिसका नाम कार्य कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा।
5. किसी गृहस्थी के सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार उतने दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए प्रत्येक आवेदक अनुरोध करे, किसी वित्तीय वर्ष में प्रति गृहस्थी अधिकतम एक सौ दिनों के अधीन रहते हुए, नियोजन के हकदार होंगे।
6. कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पैरा 5 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदक को, स्कीम के उपबंधों के अनुसार आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर या उस तारीख से, जिससे वह अग्रिम आवेदन की दशा में कार्य चाहता है, इनमें से जो भी पश्चात्कर्ती हो, अकुशल शारीरिक कार्य दिया जाएगा:

परंतु यह कि महिलाओं को इस तरह पूर्विकता दी जाएगी कि कम से कम एक तिहाई फायदा प्राप्त करने वालों में ऐसी महिलाएं होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्होंने अनुरोध किया है।

7. ²⁰स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच से संबंधित उन कार्यों से भिन्न, जिनके लिए कार्य के लिए आवेदन कम से कम छह दिन के निरंतर कार्य का होना चाहिए, कार्य के लिए आवेदन कम से कम चौदह दिनों के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए।
8. गृहस्थी की संपूर्ण हकदारी के अधीन रहते हुए नियोजन के उन दिनों की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा या उसको वस्तुतः दिए गए नियोजन के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।
9. कार्य के लिए आवेदन, लिखित रूप में ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को जैसा स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे।
10. यथास्थिति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी वैध आवेदन स्वीकार करने और आवेदक को तारीख सहित रसीद जारी करने के लिए आबद्ध होंगे। समूह आवेदन भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
11. ऐसे आवेदकों को, जिन्हें कार्य दिया जाता है, कार्य कार्ड में दिए गए उनके पते पर उनको पत्र भेज कर और जिला, मध्यवर्ती या ग्राम स्तर पर पंचायतों में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर इस प्रकार लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।
12. जहां तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर नियोजन प्रदान किया जाएगा।
13. ²¹स्कीम के अधीन कोई नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, यदि कम से कम दस श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो जाते हैं।
परंतु यह शर्त उन नए संकर्मों के लिए लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में और वनरोपण के संबंध में अवधारित किए गए हों।
14. ²²यदि नियोजन ऐसी पैरा 12 में विनिर्दिष्ट त्रिज्या बाहर प्रदान किया जाता है तो यह ब्लॉक के भीतर ही प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा।

²⁰ का0आ0 2266(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2011 द्वारा संशोधित किया गया,

²¹ का0आ0 324(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा पैरा 13 को संशोधित किया गया, (6-3-2007 से)

²² का0आ0 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा पैरा 14 के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया,

15. ²¹नियोजन की अवधि कम से कम लगातार चौदह दिन की और एक सप्ताह में छह दिन से अनधिक की होगी ।
 16. उन सभी मामलों में जहां बेकारी भत्ता संदत्त किया जाता है या संदत्त किया जाना शोध्य है वहां कार्यक्रम अधिकारी, लिखित रूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक को वे कारण सूचित करेगा कि उसके लिए आवेदको को नियोजन प्रदान करना या नियोजन प्रदान कराना क्यों संभव नहीं था ।
 17. जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परिषद् को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्टीकरण देगा कि उन मामलों में जहां बेकारी भत्ते का संदाय अंतर्वलित है, नियोजन क्यों नहीं प्रदान किया जा सका था ।
 18. स्कीम में अग्रिम आवेदन के लिए, अर्थात् ऐसे आवेदनों के लिए जो उस तारीख से जिससे नियोजन चाहा गया है, पहले प्रस्तुत किए जा सकेंगे, उपबंध किया जाएगा ।
 19. स्कीम में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने के बारे में उपबंध किया जाएगा परंतु यह तब जबकि तत्संबंधी अवधि, जिनके लिए नियोजन चाहा गया है, अतिव्याप्त नहीं होती ।
 20. ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, वाउचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, तैयार करेगी और रखेगी या तैयार करवाएगी और रखवाएगी, जिससे ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत कार्य कार्डों और जारी की गई पासबुकों की विशिष्टियां और गृहस्थी के मुखिया तथा व्यस्क सदस्यों के नाम, आयु और पते अंतर्विष्ट होंगे ।
 21. ग्राम पंचायत, उसके पास रजिस्ट्रीकृत गृहस्थियों और उनके व्यस्क सदस्यों के नाम और पते की सूचियां, ऐसी सूची तथा ऐसी अन्य जानकारियां संबद्ध कार्यक्रम अधिकारी को, ऐसी अवधि पर ऐसे प्ररूप में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भेजेगी ।
 22. उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी और सूची राज्य सरकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।
 23. यदि ग्राम पंचायत का किसी समय समाधान हो जाता हैकि किसी व्यक्ति ने मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके उसके पास रजिस्टर कराया है तो वह कार्यक्रम अधिकारी को रजिस्टर से उसका नाम काटने का निदेश दे सकेगी और आवेदक को कार्य कार्ड लौटाने का निदेश दे सकेगी:
- परंतु इस पैरा के अधीन ऐसी कार्यवाही तब तक निदेशित नहीं की जाएगी, जब तक कि आवेदक को दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया गया हो ।
24. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को, उसके नियोजन के कारण और उसके क्रम में किसी दुर्घटना से कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो वह निःशुल्क ऐसे चिकित्सीय उपचार का, जो स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है, हकदार होगा ।
 25. जहां क्षतिग्रस्त कर्मकार का अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, वहां राज्य सरकार पर उसके अस्पताल में भर्ती होने के लिए, जिसके अंतर्गत आवास, उपचार औषधियां भी हैं तथा दैनिक भत्ते के संदाय के लिए, जो संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित उस मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा, जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति के कार्य में लगे होने पर होती, व्यवस्था करेगी ।
 26. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की, नियोजन से उद्भूत दुर्घटना या उसके क्रम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उसे पच्चीस हजार रूपए की दर पर या ऐसी रकम का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जाएगा और यह रकम, यथास्थिति, मृत या निःशक्त व्यक्ति के विधिक वारिसों को संदत्त की जाएगी ।

²¹ का0आ0 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा पैरा 15 के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया,

27. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, बालकों के लिए तथा विश्राम की अवधि के लिए श्रेड, लघु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकेत के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।
28. यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ छह वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या पांच या उससे अधिक है तो ऐसी महिलाओं में से किसी एक महिला को ऐसे बालकों की देखभाल करने के लिए तैनात करने की व्यवस्था की जाएगी ।
29. पैरा 28 के अधीन नियुक्त व्यक्ति को मजदूरी दर पर संदाय किया जाएगा ।
30. यदि स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है तो श्रमिक, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे ।
- 31.²⁴ मजदूरी का भुगतान, यदि इस प्रकार छुट न दी गई हो केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मियों के बैंकों या डाकघरों में खोले गए एकल या संयुक्त बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा ।

[****].²⁵

33. यदि किसी ऐसे व्यक्ति के, जो स्कीम के अधीन नियोजित है, साथ में आने वाले बालक को दुर्घटनावश कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो ऐसा व्यक्ति बालक के लिए निःशुल्क ऐसा चिकित्सीय उपचार, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए और उसकी मृत्यु या निःशक्तता की दशा में, अनुग्रहपूर्वक संदाय, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा ।
34. स्कीम के अधीन प्रत्येक नियोजन की दशा में, मात्र लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।
- ²⁶35 (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 1, 3, 9 और 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सूनामी और भूकंप की प्रकृति के राष्ट्रीय विपत्तियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी के व्यापक विस्थापन की दशा में इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण गृहस्थियों के वयस्क सदस्य —
- (i) रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरोध कर सकेंगे और अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी कार्य कार्ड प्राप्त कर सकेंगे;
 - (ii) अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत के समक्ष कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन कर सकेंगे; और
 - (iii) हानि या विनाश की दशा में कार्य कार्ड के पुनःरजिस्ट्रीकरण और पुनःजारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

(2) सामान्य स्थिति के प्रत्यावर्तन की दशा में, इस प्रकार जारी कार्य कार्ड निवास के मूल स्थान पर पुनःपृष्ठांकित किया जाएगा और सुधार होने पर मूल कार्य कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा ।

²⁴ का0आ0 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012 द्वारा पैरा 14 के स्थान पर अंतःस्थापित किया गया, इसके पहले का0आ0 513(अ), तारीख 19 फरवरी, 2009 द्वारा संशोधित किया गया था,

²⁵ का0आ0 513(अ), तारीख 19 फरवरी, 2009 द्वारा पैरा 32 का लोप किया गया,

²⁶ का0आ0 2188(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2008 द्वारा पैरा 35 को जोड़ा गया,

(3) इस प्रकार उपलब्ध कराए गए नियोजन के दिनों की संख्या की गणना, प्रति गृहस्थी 100 दिनों की गारंटीकृत नियोजन की संगणना करते समय की जाएगी।²⁷

38. अधिनियम या उसमें अनुसूची के अधीन प्राप्त शिकायतों या स्वप्रेरणा और अन्यथा उपबंधित से लिए गए संज्ञान पर निम्नलिखित रीति में कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् : —

- (क) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को उसके द्वारा रखे गए शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और शिकायत की अभिस्वीकृति सम्यक् रूप से संख्यांकित और तारीख सहित जारी करेगा;
- (ख) स्थल पर सत्यापन के माध्यम से जांच, निरीक्षण और निपटारा सात कार्यदिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा;
- (ग) किसी ग्राम पंचायत द्वारा जो उस कार्यक्रम अधिकारी की अधिकारिता के भीतर आती है, शिकायतों का इसके अंतर्गत अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतें भी हैं, उनका अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन यथा विहित सात दिन के भीतर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निपटारा किया जाएगा और यदि उस दशा में जब शिकायत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हल किए जाने के विषय से संबंधित है, तो कार्यक्रम अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा और विषय को ऐसे प्राधिकारी को शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए सात दिन के भीतर निर्दिष्ट करेगा;
- (घ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सात दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करने में व्यतिक्रम होने पर अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा और अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय होगा तथा ऐसी चूक के विरुद्ध शिकायतें जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास फाइल की जाएगी;
- (ङ) वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने की दशा में, जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल की गई है;
- (च) राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या प्रतिनिर्देश से किसी शिकायत की जांच कर सकेगा और दोषी साबित होने पर, दोषी पर अधिनियम की धारा 25 के अधीन शास्ति अधिरोपित करेगा;
- (छ) यदि संबद्ध प्राधिकारी यह पाता है कि हकदारी का उल्लंघन है, तो वह व्यथित पक्षकार को सूचना देगा और पंद्रह दिन के भीतर ऐसी शिकायत के समाधान के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ज) की गई कार्यवाही के संबंध में शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा और एक पखवाड़े में एक बार विहित फार्मेट में दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगा;
- (झ) कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही क्रमशः मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखी जाएगी;
- (ञ) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील कार्यक्रम अधिकारी को की जाएगी और वे जो कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक को की जाएगी तथा जो जिला कार्यक्रम समन्वयक के विरुद्ध हैं, वे राज्य आयुक्त (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम) को की जाएगी;
- (ट) खंड (ञ) के अधीन कोई अपील आदेश पारित किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर की जाएगी; और
- (ठ) उसकी प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर किसी अपील का निपटारा किया जाएगा।²⁸

²⁷ का0आ0 2999(अ). तारीख 31 दिसम्बर, 2008 द्वारा पैरा 36 को जोड़ा गया.